MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Minister to move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, we are going to take up the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, this is a very important Bill ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let the motion be moved. Shri Prakash Javadekar to move the motion for consideration.

The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, I move:

That the Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration ...*(Interruptions)*...

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: Mr. Jha, you are not going through the agenda. This item is coming afterwards. Please understand and cooperate ...*(Interruptions)*... You are not seeing what I am going to say next. You please sit down. Don't protest. Have patience. Hereafter, there is one amendment by Shri Husain Dalwai for reference of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018 to a Select Committee of the Rajya Sabha. The Member may move his amendment at this stage without any speech. Mr. Husain Dalwai, are you moving the amendment?

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): Sir, I am not moving the amendment. I am withdrawing it.

MR. CHAIRMAN: Thank you. The motion for consideration of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018, as passed by Lok Sabha, and as moved by the Minister, is open for discussion. Any Member who wants to speak, may do so after the Minister. ...*(Interruptions)*... Derekji, you are a very senior

[Mr. Chairman]

Member. After great difficulty, after so many days, we started taking up a Bill. You have only Monday, and then afterwards, every day will be Sunday till the next Session. So, keeping that in mind, let us take it up to the extent possible.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, you extend the time of the House.

MR. CHAIRMAN: Here, we are not ready to sit during the Session!

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI VIJAY GOEL): Sir, I propose to extend the time of the House for one hour.

MR. CHAIRMAN: Yes. See, depending on the situation, if necessary, we will extend. Shri Mahesh Poddar ...*(Interruptions)*... Mr. K.K. Ragesh, not now. Please. I will give you time afterwards ...*(Interruptions)*... Just now, he said, 'time is extended'. Time is three hours only ...*(Interruptions)*... It is there in the List. Have patience. I have no problem to sit up to 10.30 p.m., 11.30 p.m. or 12.30. ...*(Interruptions)*... Silence, please. People who have got some important work, in order to talk, they can go out, take advantage of the washroom, and then discuss, and come back.

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Mahesh Poddar.

SHRI MAHESH PODDAR (Jharkhand): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018. ...*(Interruptions)*... The Right to Education Act, 2009 prohibits detention of children till they complete elementary education, that is, class VIII. The Bill amends this provision to state that a regular examination will be held in class 5 and class 8 at the end of every academic year. If a child fails in the examination, he will be given additional instruction, and he can take a re-examination.

If he fails in the re-examination, the concerned Central or State Governments may decide to allow schools to detain the child.

This new piece of legislation has been brought to the House after substantial deliberations and manifold consultations with all the States, Union Territories and other stakeholders. The detention provision has been examined by three different committees. All the committees have endorsed the Bill in its current form.

6.00 P.M.

The enactment of the Right to Education Act, 2009 initially focused on quantitative expansion of education with focus on optimum enrolment, school buildings, infrastructure," etc., and while doing so, the quality aspects of teaching and learning remained on back stage. This has led us to a situation which necessitates the review of the Act.

It is a fact which cannot any longer be ignored. The National Council of Education, Research and Training (NCERT), National Achievement Survey or Annual Status of Education Report (ASER) have consistently revealed the abysmally-low learning levels among school children. It is a cause of serious concern for the Committee. Further, with the no detention policy, there is no pressure on the children to learn and on the teachers to teach.

MR. CHAIRMAN: Please don't read. If you want to say something, you have to speak.

श्री महेश पोद्दार: सर, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और हमारा देश विविधताओं का देश है। इस लिहाज से हर राज्य की अपनी-अपनी विशेषतएं और विवशताएं हैं। इसलिए जैसा कि विद्वान सलाहकारों ने सुझाव भी दिया है कि इस मामले में अंतिम निर्णय राज्य की सरकारों पर छोड़ दिया जाए, इसका मतलब यह भी नहीं है कि केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर कोई अपनी राय नहीं रखेगी या तटस्थ हो जाएगी।

सर, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कुछ रिसर्च बताती हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में ड्रॉप रेट कम है, लेकिन उच्चतर कक्षाओं में ड्रॉप रेट ज्यादा है। माफ कीजिएगा, लेकिन यह कड़वी और दारुण सच्चाई मुझे सदन में रखनी ही पड़ेगी और इसकी एक वजह मिड-डे मील भी है। लेकिन जो चीज़ खुली आंखों से दिखती है, उसका ज़िक्र अवश्य करना चाहिए। इस क्रम में, मैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करना प्रासंगिक मानता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा परियोजना के तहत लगभग सभी प्रदेशों में अनुबंध पर टीचरों की नियुक्ति हुई है।

महोदय, कहीं शिक्षा मित्र तो कहीं पैरा टीचर के नाम पर उन्हें लिया गया है। राज्यों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस सदन में बैठे हर सदस्य को पता है कि उनके राज्य में इन अनुबंधित शिक्षकों की बहाली कैसे हुई और बहाली के क्रम में योग्यता का कितना ध्यान रखा गया है और इनमें से कितने प्रशिक्षित हैं, इत्यादि-इत्यादि।

महोदय, ज्यादातर प्रदेशों में नियमित शिक्षकों की कमी के कारण अनुबंधित पैरा टीचर्स ही ड्राइविंग सीट पर हैं, लेकिन आज स्थिति यह है हमारे झारखंड राज्य में तो ऐसे लोग हड़ताल पर भी हैं। ये हड़ताल पर इसलिए हैं कि यदि कानूनी प्रतिबंध के बिना बच्चे ज्ञान प्राप्त किए बिना, अगली कक्षा में प्रोन्नत होते जाते हैं, तो समझ लीजिए कि हम भारत का भविष्य कैसा कर रहे हैं।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा विषय है, जिसमें निरंतर सुधार की संभावनाएं हैं और हमें इस दिशा में हर समय निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपनी पार्टी की तरफ से सदन के सामने जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल का जो मूल उद्देश्य है, वह छोटी क्लासों में, प्राइमरी शिक्षा में बच्चों को फेल करना या डिटेन करना नहीं है। बड़े लम्बे संघर्षों के बाद हमारे देश में शिक्षा का अधिकार दिया गया और वर्ष 2002 में संविधान में संशोधन किया गया तथा वर्ष 2009 में राइट टू एजुकेशन के नाम से एक एक्ट संसद में पारित किया, जिसके अंदर यह व्यवस्था की गई कि कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो हर बच्चे को, चाहे वह देश के किसी भी भाग में पैदा हुआ हो, चाहे वह किसी भी वर्ग में पैदा हुआ हो और चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, उसे देने का काम करेंगे।

महोदय, जब मैं छात्र राजनीति में आया था और इस सदन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने ये नारे लगाए थे कि शिक्षा अधिकार है, सुविधा नहीं है और यह सिर्फ संभ्रान्त लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का इस पर मौलिक अधिकार होना चाहिए।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

उपसभापति जी, हमारे देश के अंदर समाजवादी आन्दोलन के नेता डा. राम मनोहर लोहिया जी ने भी एक समय नारा दिया था कि

"हो गरीब या हो बलवान, शिक्षा होगी एक समान"

इस देश में सबको शिक्षा देने की वकालत समाजवादियों ने की थी। इसी तरीके से वर्ष 2009 में जाकर यह अधिकार मिला कि बच्चे शिक्षा हासिल करेंग। इसी आर.टी.ई. एक्ट में एक महत्वपूर्ण क्लॉज नंबर 16 है, जिसे आज संशोधित किए जाने की बात माननीय मंत्री जी की तरफ से आई है। इसमें यह व्यवस्था है कि प्राइमरी में दाखिला लेने के बाद कक्षा आठ तक उस बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, बल्कि लगातार उसे अगली क्लास में उन्नति दी जाएगी। उसमें परीक्षा का जिक्र नहीं था, बल्कि उसमें continuous and comprehensive evaluation की व्यवस्था थी। जब आप परीक्षा लेंगे, तो फिर पुरानी व्यवस्था में लौट जाएंगे, जो व्यवस्था आरटी एक्ट के लागू होने से पहले हमारे देश में लागू थी और जिसमें बच्चे फेल भी होते थे और पास भी होते थे। मैं कहना चाहता हूं कि आज फेल और पास होने की जिम्मेदारी हम छोटे बच्चों पर, अबोध बालकों पर, जो बिल्कुल मासूम हैं और जो ज्यादा जानते नहीं हैं, उनके ऊपर नहीं डाल सकते, बल्कि बच्चों के बारे में यह जिम्मेदारी व्यवस्था की है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की है - वह इस बात का इंतजाम करे कि बच्चे आगे शिक्षा ग्रहण करते हुए उस स्तर को पार करते हुए कक्षा पांच या आठ में जाएं, यह उम्मीद उनसे की जाती है। ...**(व्यवधान)**... मैं समझता हूं कि अगर इस बिल को पास किया जाता है और छोटी क्लासों में परीक्षा की अनिवार्यता स्थापित कर दी जाएगी, तो निश्चित रूप से स्कूलों में ड्रॉपआउट बढ़ेगा। जब यह व्यवस्था नहीं थी, तब हम पहले देखते थे, गांवों के अंदर, जहां कमजोर तबकों के बच्चे शिक्षा लेने जाते थे, खास तौर से सरकारी स्कूलों में, उनमें ड्रॉपआउट की दर बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन जो पब्लिक स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उनके अंदर ड्रॉपआउट की समस्या लगभग न के बराबर होती थी। अगर हम उसी व्यवस्था को दोबारा से लागू कर देंगे, तो निश्चित रूप से उन प्राइमरी स्कूलों में, जो सरकारी क्षेत्र में चल रहे हैं, उनमें ड्रॉपआउट की समस्या बढ़ेगी।

मान्यवर, आप यह भी जानते हैं कि आज सरकारी स्कूल किन वर्गों तक सीमित हैं। उनमें कमजोर तबकों के बच्चे जाते हैं, उनमें दलितों के बच्चे जाते हैं, गाँव-देहात में रहने वाले पिछड़ों और गरीबों के बच्चे जाते हैं, उनमें अल्पसंख्यकों के बच्चे जाते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि आप अपनी व्यवस्था को ठीक कीजिए। आप छोटे बच्चे पर परीक्षा को पास करने की जिम्मेदारी मत डालिए। आप अपने अध्यापकों को इस किस्म की ट्रेनिंग दीजिए, अभी आपने पिछले बिल में जिक्र भी किया है कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे उस बच्चे का सही विकास हो सके। आप अभी उस बच्चे की परीक्षा मत लीजिए, वह बच्चा अभी चौदह साल से भी कम का है। उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना कि वह पास होगा या फेल होगा, मैं समझता हूं कि यह बात उसके बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करेगी।

महोदय, हमारे स्कूलों का माहौल बहुत खराब है। आज देश के अंदर प्राइमरी एजुकेशन की जो हालत है, खास तौर से सरकारी क्षेत्र में चलने वाले प्राइमरी विद्यालयों की जो हालत है, उसको हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हज़ारों स्कूल ऐसे हैं, जिनमें एक अध्यापक भी नहीं है। अखिलेश जी ने शिक्षामित्र लगाए थे, लेकिन कोर्ट का एक आदेश आया और उसके बाद 1 लाख, 72 हज़ार शिक्षामित्र, जो किसी तरीके से उन विद्यालयों को संचालित कर रहे थे, बच्चों को तालीम दे रहे थे, वे सब सड़क पर आ गए। पिछले वर्ष एक विषय पर बोलते हुए हमने मंत्री जी से भी अनुरोध किया था और उनसे दरख्वास्त की थी, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि केन्द्र सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज तक न तो राज्य सरकार की तरफ से, न केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कारगर हस्तक्षेप शिक्षामित्रों की बहाली के लिए या उनको सम्मानजनक स्थान देने के लिए, उनको दोबारा से शिक्षा की धारा में लाने के लिए और पढ़ाने के लिए अभी तक हुआ है।

सर, उत्तर प्रदेश में हालात यह है कि हमारी जो महिला शिक्षिकाएं थीं, जो शिक्षामित्र थीं, वे आंदोलन पर हैं। सैंकड़ों महिलाओं ने विरोधस्वरूप अपने बाल तक मुंडवा लिए, लेकिन सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। ऐसा कोई कानून न तो उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर और न केंद्र सरकार के स्तर पर बना है, जिससे शिक्षामित्रों का कुछ भला हो सके।

महोदय, मैं शिक्षामित्रों की बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि जब आपके स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं होंगे, शिक्षामित्र तक नहीं होंगे, तब आप उस अबोध बच्चे पर फेल होने या पास होने की जिम्मेदारी कैसे निर्धारित कर सकते हैं? आज स्कूलों में माहौल इतना खराब है कि जितने समय वहां शिक्षा होनी चाहिए, उतने समय नहीं हो रही है। यदि आज कोई मेरे ही गाँव में प्राइमरी स्कूल में जाकर देख लेगा, तो पाएगा कि वहां अध्यापक आधा टाइम तो खाना बनाने में गुजार देते हैं। क्यों गुजार देते हैं? आपने वहां जो रसोइए रखे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। आप उन्हें 1 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन आपके प्राइमरी स्कूल में सफाई करने वाला एक भी कर्मचारी नहीं होता। वे पहले रसोइए से स्कूल की सफाई करवाते हैं, फिर बर्तन धुलवाते हैं और फिर खाना बनवाते हैं। ...**(व्यवधान)**...

†

جناب جاوید علی خان (اترپردیش): مانیئے سبھاپتی جی، مانیئے منتری جی نھے اپنی پارٹی کی طرف سے سدن کے سامنے جو بل پیش کیا ہے، میں اس پر بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اس بل کا جو مول اُدیش ہے، وہ چھوٹی کلاسوں میں،

†Transliteration in Urdu script.

[श्री जावेद अली खान]

پرائمری شکشکا میں بچوں کو فیل کرنا یا ڈیٹین کرنا ہے۔ بڑے لمبے سنگھرشوں کے بعد ہمارے دیش میں شکشا کہ ادھیکار دیا گیا اور سال 2002 میں سمودھان میں سنشودھن کیا گیا تتھا سال 2009 میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کے نام سے ایک ایکٹ سنسد نے پاس کیا، جس کے اندر یہ ویوستھا کی گئی کہ کم سے کم پرائمری ایجوکیشن تو ہر بچے کو، چاہے وہ دیش کے کسی بھی بھاگ میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے میں پیدا ہوا ہو اور چاہے کسی بھی دھرم میں پیدا ہوا ہو، اسے دینے کا کام کریں گے۔

مہودے، جب میں چھاتر راجنیتی میں آیا تھا اور اس سدن کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے کہ شکشا ادھیکار ہے، سُویدھا نہیں ہے اور یہ صرف سمبھرانت لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کا اس پر مولک ادھیکار ہونا چاہئیے۔

(شری اُپ سبھاپتی صدر نشیں ہوئے)

اُپ سبھاپتی جی، ہمارے دیش کے اندر سماج وادی آندولن کے نیتا ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نے بھی ایک وقت نعرہ دیا تھا کہ ؎

"ہو غریب یا ہو بلوان، شِکشا ہوگی ایک سمان"

اس دیش میں سب کو تعلیم دینے کی وکالت سماجوادیوں نے کی تھی۔ اسی طریقے سے سال 2009 میں جاکر یہ ادھیکار ملا کہ بچے تعلیم حاصل کریں گے۔ اسی آر ٹی ایکٹ میں ایک اہم کلاز نمبر 16 ہے، جسے آج ترمیم کئے جانے کی بات مانیئے منتری جی کی طرف سے آئی ہے۔ اس میں یہ ویوستھا ہے کہ پرائمری میں داخلہ لینے کے بعد آٹھویں کلاس تک اس بچے کو فیل نہیں کیا جائےگا، بلکہ

لگاتار اسے اگلی کلاس میں ترقی دی جائے گی۔ اس میں امتحان کا ذکر نہیں تھا، بلکہ اس میںcontinuous and comprehensive evaluation کی ویوستھا تھی۔ جب آپ امتحان لیں گے، تو پھر پرانی ویوستھا میں لوٹ جائیں گے، جو ویوستھا آرٹی ایکٹ کے لاگو ہونے سے پہلے ہمارے دیش میں لاگو تھی اور جس میں بچے فیل بھی ہوتے تھے اور پاس بھی ہوتے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج فیل اور پاس ہونے کی ذمہ داری ہم چھوٹے بچوں پر، ابودھ بالکوں پر، جو بلکل معصول ہیں اور جو بہت زیادہ جانتے نہیں ہیں، ان کے اوپر نہیں ڈال سکتے، بلکہ بچوں کے بارے میں یہ ذمہ داری ویوستھا کی ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی ہے۔ وہ اس بات کا انتظام کرے کہ بچے آگے شکشا گرہن کرتے ہوئے اس استر کو پار کرتے ہوئے پانچویں کلاس میں یا آٹھویں میں جائیں، یہ امید ان سے کی جاتی ہے۔ ...(مداخلت)...

میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بل کو پاس کیا جاتا ہے اور چھوٹی کلاسوں میں پریکشا کی انیوارئیتا استھاپت کر دی جائے گی، تو نشچت روپ سے اسکولوں میں ڈراپ آؤٹ بڑھے گا۔ جب یہ ویوستھا نہیں تھی، تب ہم پہلے دیکھتے تھے، گاؤں کے اندر، جہاں کمزور طبقوں کے بچے شکشا لینے جاتے تھے، خاص طور سے سرکاری اسکولوں میں، ان میں ڈراپ آؤٹ کی در بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن جو پبلک اسکول ہیں یا پرائیوٹ اسکول ہیں، ان کے اندر ڈراپ آؤٹ کی سمسیہ لگ بھگ نہ کے برابر ہوتی تھی، اگر ہم اسی ویوستھا کو دوبارہ سے لاگر کر دیں گے۔ تو نشچت روپ سے ان پرائمری اسکولوں میں، جو سرکاری چھیتر میں چل رہے ہیں، ان میں ڈراپ آؤٹ کی سمسیہ بڑھے گی۔

مانیور، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج سرکاری اسکول کن ورگوں تک سمیت ہیں۔ ان میں کمزور طبقوں کے بچے جاتے ہیں، ان میں دلتوں کے بچے جاتے ہیں، گاؤں دیہات میں رہنے والے پچھڑوں اور غریبوں کے بچے جاتے ہیں، ان میں

[श्री जावेद अली खान]

اقلیتوں کے بچے جاتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ویوستھا کو ٹھیک کیجئے۔ آپ چھوٹے بچے پر پریکشا کو پاس کرنے کی ذمہ داری مت ڈالئے۔ آپ اپنے ادھیاپکوں کو اس قسم کی ٹریننگ دیجئے، ابھی آپ نے پچھلے بل میں ذکر بھی کیا ہے کہ ایسی ویوستھا ہو جس سے اس بچے کا صحیح وکاس ہو سکے۔ آپ ابھی اس بچے کی پریکشا مت لیجئے، وہ بچہ ابھی چودہ سال سے بھی کم کا ہے۔ اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالنا کہ وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا، میں سمجھتاہوں کہ یہ بات اس کے بودھک وکاس کو بھی پربھاوت کرے گی۔

مہودے، ہمارے اسکولوں کا ماحول بہت خراب ہے۔ آج دیش کے اندر پرائمری ایجوکیشن کی جو حالت ہے۔ خاص طور سے سرکاری چھیتر میں چلنے والے پرائمری ودھیالیوں کی جو حالت ہے، اس کو ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اتّر پردیش کے اندر ہزاروں اسکول ایسے ہیں، جن میں ایک ادھیاپک بھی نہیں ہے۔ اکھلیش جی نے شکشا متر لگائے تھے، لیکن کورٹ کا ایک آدیش آیا اور اس کے بعد 1 لاکھہ، 72 ہزار شکشا متر، جو کسی طریقے سے ان ودھیالیوں کو سنچالت کر رہے تھے، بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، وہ سب سڑک پر آ گئے۔ پچھلے سال ایک وشئے پر بولتے ہوئے ہم نے منتری جی سے بھی انورودھہ کیا تھا اور ان سے درخواست کی تھی، انہوں نے ہمیں آشواسن بھی دیا تھا کہ کیندر سرکار اس معاملے میں کوئی ہستکشیپ کرے گی، لیکن اتّر پردیش میں آج تک نہ تو راجیہ سرکاری کی طرف سے، نہ کیندر سرکاری کی طرف سے کوئی کارگر ہستکشیپ شکشا متروں کی بحالی کے لئے یا ان کو سمان جنک استھان دینے کے لئے، ان کو دوبارہ سے شکشا کی دھارا میں لانے کے لئے اور پڑھانے کے لئے ابھی تک ہوا ہے۔

سر، اتّر پردیش میں حالت یہ ہے کہ ہماری جو مہیلا شکشکائیں تھیں، جو شکشا متر تھیں، وہ آندولن پر ہیں، سینکڑوں مہیلاؤں نے مخالفت کے طور پر اپنے بال تک منڈوا لئے، لیکن سرکار کے کان پر کوئی جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ ایسا کوئی قانون نہ تو اتر پردیش سرکار کے استر پر اور نہ کیندر سرکار کے استر پر بنا ہے، جس سے شکشا متروں کا کچھہ بھلا ہو سکے۔

مہودے، میں شکشا متروں کی بات اس لئے کر رہا ہوں، کیوں کہ جب آپ کے اسکول میں پڑھانے والے ٹیچرس نہیں ہوں گے، شکشا متر تک نہیں ہوں گے، تب آپ اس ابودھہ بچے پر فیل ہونے یا پاس ہونے کی ذمہ داری کیسے نردھارت کر سکتے ہیں؟ آج اسکولوں میں ماحول اتنا خراب ہے کہ جتنے وقت یہاں شکشا ہونی چاہئے، اتنے وقت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آج کوئی میرے ہی گاؤں میں پرائمری اسکول میں جاکر دیکھہ لے گا، تو پائے گا کہ وہاں ادھیاپک آدھا ٹائم تو کھانا بنانے میں گزار دیتے ہیں۔ کیوں گزار دیتے ہیں؟ آپ نے وہاں جو رسوئیے رکھے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ انہیں ایک ہزار روپے دیتے ہیں، لیکن آپ کے پرائمری اسکول میں صفائی کرنے والا ایک بھی کرمچاری نہیں ہوتا۔ وہ پہلے رسوئیے سے اسکول کی صفائی کرواتے ہیں، پھر برتن دھلواتے ہیں اور پھر کھانا بنواتے ہیں ...(مداخلت)...

श्री उपसभापति: माननीय जावेद साहब, समाप्त कीजिए।

श्री जावेद अली खान: वह ज्यादा काम कर नहीं पाता है, इसलिए मास्टर साहब को भी उसमें लग जाना पड़ता है, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर हम बच्चों के ऊपर इतनी छोटी उम्र में परीक्षा का बोझ डाल देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे स्कूलों का ड्रॉपआउट बढ़ेगा और स्कूल बंद होंगे। आज कई राज्यों में हजारों की तादाद में प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं या फिर सरकार ने एक स्कीम निकाली है, जिसमें वह दो विद्यालयों को merge कर देती है। नीति आयोग की तरफ से भी कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं कि इन विद्यालयों की समीक्षा की जाए और ज्यादा से ज्यादा हमें इनके merger पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें outcome देना है। Outcome विद्यालय को merge करके नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चों को पढ़ाकर उनको अच्छी तालीम देकर और स्कूल का माहौल अच्छा करके देना चाहिए।

आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। हमारे दल के नेता, प्रोफेसर साहब यहां से चले गए, वे एक बात कहते हैं। हम लोग बहुत दिनों से पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम

[श्री जावेद अली खान]

करते रहे हैं। हम प्रोफेसर साहब से कहते थे कि हमारा कब भला होगा, तो प्रोफेसर साहब हमसे कहते थे कि पड़े रहो अखाड़े में, अगर अखाड़े में पड़े रहोगे, तो एक दिन पहलवान जरूर बन जाओगे और आज हम राज्य सभा में आ गए। मैं कहता हूं कि इन बच्चों को स्कूल से मत निकालिए। अगर ये स्कूल में आठवीं क्लास तक पड़े रहेंगे, तो वहां से कुछ न कुछ थोड़ा-बहुत तो सीख कर ही निकलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

† **جناب جاوید علی خان:** وہ زیادہ کام کر نہیں پاتا ہے، اس لیے ماسٹر صاحب کو بھی اس میں لگ جانا پڑتا ہے، پڑھائی تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بچوں کے اوپر اتنی چھوٹی عمر میں امتحان کا بوجھ ڈال دیں گے، تو نِشچت روپ سے ہمارے اسکولوں کا ڈراپ آؤٹ بڑھے گا اور اسکول بند ہونگے۔

آج کئی راجیوں میں ہزاروں کی تعداد میں پرائمری اسکول بند ہوچکے ہیں یا پھر سرکار نے ایک اسکیم نکالی ہے، جس میں وہ دو اسکولوں کو merge کردیتی ہے۔ نیتی آیوگ کی طرف سے بھی کچھ اس طریقے کی رپورٹس آئی ہیں کہ ان اسکولوں کی سمیکشا کی جائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں ان کے merger پر دھیان دینا چاہیئے، کیوں کہ ہمیں outcome دینا ہے۔ Outcom اسکول کو merge کرکے نہیں دینا چاہیے، بلکہ بچوں کو پڑھاکر، ان کو اچھی تعلیم دیکر اور اسکول کا ماحول اچھا کرکے دینا چاہیئے۔

آخر میں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ہمارے دل کے نیتا، پروفیسر صاحب یہاں سے چلے گئے، وہ ایک بات کہتے ہیں۔ ہم لوگ بہت دنوں سے پارٹی میں راجنیتک کارنیےکرتا کے روپ میں کام کرتے رہے ہیں۔ ہم پروفیسر صاحب سے کہتے تھے کہ ہمارا کب بھلا ہوگا، تو پروفیسر صاحب ہم سے کہتے تھے کہ پڑے رہو اکھاڑے میں، اگر اکھاڑے میں پڑے رہوگے، تو ایک دن پہلوان ضرور بن جاؤ گے اور آج ہم راجیہ سبھا میں آگئے۔ میں کہتا ہوں کہ ان

†Transliteration in Urdu script.

بچوں کو اسکول سے مت نکالئیے۔ اگر یہ اسکول میں آٹھویں کلاس تک پڑھے رہیں گے، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو سیکھ کر ہی نکلیں گے۔

بہت بہت دھنیواد۔

(ختم شد)

श्री उपसभापति: धन्यवाद माननीय जावेद अली खान साहब। माननीय मो. नदीमुल हक जी।

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Respected Deputy Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak on this Bill which amends the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Sir, first of all, I have to remind this House that in 1976, education by the 42nd Constitutional Amendment was taken out of the State List and put into the Concurrent List. Sir, here, is it worth thinking whether it can be put back, especially in the spirit of cooperative federalism? Can it be put back into the State List? I ask the Minister to consider this. Sir, standardised testing is part of a bureaucracy that adds layers of surveillance mechanisms and procedures for students to follow. These examinations constrain our youth's possibilities and freedom. Good students are shown to be smart and successful standardised test-takers, their talents and cocurricular performances are largely ignored. The media, coaching industry and society including peers play a part in perpetuating this pressure, thus creating a self-sustaining cycle. Under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, no child can be held back in any class until the completion of elementary school, *i.e.* Classes I to VIII. The Bill amends this provision to empower the Central or State Governments to allow schools to hold back a child in Class V, Class VIII, or in both classes. Sir, examinations go beyond impacting children. It also changes the nature of teaching, narrows the curriculum, and limits student learning. Teachers' tasks increase because they take up work related to teaching in addition to their regular teaching duties. As a result, teachers have less time for teaching. Standardised tests also narrow the entire curriculum in many schools, often leaving out subjects such as music, arts and sports, especially in elementary grades because they are not included in tests. Most importantly, standardised tests limit student learning because they focus only on cognitive dimensions, ignoring many other qualities that are essential to a student's success. These examinations have different effects on various populations of students, and they usually lead to significant limits on learning among poor and minority students. For example, the scores of poor and minority students are often lower than their peers from better off socio-economic background, and these results can lead to a failure of recognising their potential. Children primarily undergo stress due to two factors. The first is the hype that surrounds the board examinations. At present, if you see, from the time students enter Class IX, the pressure is relentless to perform in time for the boards. The Bill has now preponed this stress by another five years. Now,

[Shri Md. Nadimul Haque]

the scores in Class V will be held as a certification of the child's potential. The second cause of stress is students' inherent belief in their own capabilities. Given the hype and pressure created, it is easy to start doubting one's own capacity. Coupled with immense amount of peer comparisons, large amounts of curricular material and long, continuous periods of focussed study, stress generation is inevitable. Students continuously study and memorize large amounts of information. Thus, careful consideration needs to be given to student's mental state throughout the year. Professional help is difficult to find, because India endures an acute shortage of mental health professionals. There are only 898 psychologists against 20,250 required in the country and less than 900 psychiatric social workers against 37,000 needed. Mental healthcare is a much neglected area in our country. To cater to a population of 1.3 billion, India only has about 0.3 mental health professionals and 10 hospital beds per one lakh people!

Most Western countries spend 4 per cent of their budget on mental health, while India spends only 0.4 per cent! Failing in exams or inability to cope with academics is the primary reason for suicide by students. This step to test children at such a young age calls for mental health and wellness to be added to school curriculum. Student counselling must be made accessible to every child enrolled in school before another set of board examinations add to the existing stress on children.

Finland, for example, routinely tops rankings of global education systems and is famous for having no banding system. All students, regardless of ability, are taught in the same class.

Sir, on the education front, West Bengal has been making rapid strides and progress in the last seven years under Mamta Banerjee's Government. Many of the successes which have proven in Bengal can be initiated or replicated at the national level.

The present system of education and examination itself is a major hindrance for child development in India. Standardised testing through board examinations in Class V and VIII goes on to institutionalize stress on children before they are even old enough to understand the crux of these examinations, let alone handle the pressure.

Ultimately, this categorises some youth as 'un-smart' in contrast to an ideal smart citizen. In an age where multiple literacy and talents are more and more valued, standardised testing acts as a form of social control. The objective testing has become a normal mechanism to test, monitor and improve child's performance. The idea is to help identify those youth who are not maximizing their potential and may not be productive citizens.

Sir, I wish to add a couplet here.

"हम से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तो
सब कुछ जो जानते हैं, वो कुछ जानते नहीं।"

†"حد سے بڑھے جو علم تو ہے جہل دوستوں
سب کچھ جو جانتے ہیں، وہ کچھ جانتے نہیں"

Sir, with these observations, I support this Bill, but with caution. The Government must, therefore, not merely limit its role in taking examinations, but contribute to the holistic development and well-being of the child. Thank you.

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, when we were students, particularly those students who studied science, we were having dissection of frog to know what our insight is. I think, we are doing dissection on our own students. I don't understand why we change our policy on education and examination time and again. What is the reason? We had made an amendment to the Act in 2009. We had adopted No Detention Policy in 2009 which has been implemented since 2010. I would like to know from the hon. Minister that in how many schools of the country the No Detention Policy has been adopted between 2010 and 2018.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I will explain it.

SHRI PRASANNA ACHARYA: How could the Government come to a conclusion whether this has succeeded or failed? So, this is my basic question to the hon. Minister. As such, I support this Amendment Bill. I am personally in favour of examination and detention because this is a competitive world. Wherever you go — within your small town, within your State, within the country, outside the country — you face competition. So, we have to build up the mind and psychology of our students to face this competitive world. Only fittest of the fit can survive in this competitive world. So, through examination, we should build up their mind to face a bigger competition in the future life. Therefore, in my personal opinion, the detention policy is good. There is no doubt in it. But, changing the policy time and again is not good.

But, as some of the hon. Members were raising the issue of infrastructure, we cannot decide the future of our students only on the basis of our examination policy. What is our infrastructure in education? How much of our GDP we are spending on education? If I remember, the Kothari Commission had in 1966 recommended the spending of 6 per cent of our GDP on education. How much are you spending? I think, it is 3.7 per cent

†Transliteration in Urdu script.

[Shri Prasanna Acharya]

or maximum 4 per cent of our GDP. So, how can you build up infrastructure? In the rural areas, there are a large number of schools without proper infrastructure. And, as some of the hon. Members were pointing out, there are not even sufficient teachers in many schools. If there is a requirement of five teachers, there are only two teachers. One teacher is taking care of three classes. So, how can you expect the students to do better? Therefore, before you decide whether you should go with the detention policy or whether you dispose of the detention policy, you have to strengthen the infrastructure.

Then, without examinations, how can a teacher find out the weak points of the students? Therefore, examinations are necessary. An examination is a testing point which let you know where a student is lagging. Thus, you will be able to take care of those weaknesses in the students. You cannot do that without examinations.

There is an argument that if you give up the detention policy, the dropout rate will increase. But, if you go through the report, after you implemented the detention policy, I think, the dropout has increased; it has not gone down. Therefore, examination is not the reason behind dropout. Therefore, I think, the examination policy should continue. When I was in the primary school, we would face examinations in each and every class, not only in fifth and eighth standards. We would appear in examinations in class I, class II, class III, class IV, and class V, all the classes. And, with that system, many talents have come out in this country. Swami Vivekananda was also a product of that system. Many talented people, great intellectuals, of this country are the products of this old system. So, in a nutshell, I will cut it short because one more Member from my party has to speak, there should be the examination system. But, that alone is not enough. You have to develop the infrastructure. You have to spend more on account of education. Without that, only by changing the examination system, you are not going to solve the problem.

With these words, Sir, I support this Bill.

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): माननीय उपसभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 पर बोलने का अवसर दिया। नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में यह प्रावधान किया गया था कि प्रारम्भिक शिक्षा, अर्थात् वर्ग 1 से 8 तक किसी भी बच्चे को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी वर्ग में नहीं रोका जाएगा, विशेषकर वर्ग 5 और 8 - इन दोनों वर्गों में कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इस संशोधन विधेयक के द्वारा मूल अधिनियम में संशोधन करके केन्द्र या राज्य सरकार को यह अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया है कि यदि वे चाहें तो अपने विद्यालयों को वर्ग 5 और 8 अथवा दोनों वर्गों में बच्चों को रोकने की अनुमति दे सकते हैं।

महोदय, प्रतिस्पर्धा के इस युग में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। फेल न करने की नीति और जिस कक्षा में बच्चा असफल हो जाता है, उस कक्षा में बच्चे को न रोके जाने से बच्चे का ही नुकसान होता है। बच्चा पढ़ाई में कमजोर रह जाता है और अगली कक्षा में चला जाता है। तत्पश्चात् अगली कक्षा में फिर वही स्थिति रहती है। नतीजतन बच्चा कमजोर ही रह जाता है और जब वह किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, फिर भी रोज़गार पाने योग्य नहीं रहता।

महोदय, कमज़ोर बुनियाद पर मजबूत किले नहीं बनाए जा सकते। इसलिए यह प्रस्ताव ठीक है कि पहली बार में असफल बच्चों को दो मास में ही दूसरा अवसर उपलब्ध कराने के बावजूद असफल रहने पर ऐसे बच्चों को रोका जाना सही कदम होगा ताकि फिर से वे मेहनत करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और विषयों पर उनकी पकड़ मजबूत हो सके। इस क्रम में यह आवश ध्यान रखना चाहिए कि इससे बच्चों में किसी प्रकार के भय, तनाव या अवसाद का माहौल न बन सके, बच्चों पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव न क्रिएट हो। इन शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, I stand to oppose this Bill *per se,* because through this Bill, unfortunately, the Government is trying to reinstate the older detention policy as a remedy to low quality in school education. We all know that as far as the school education is concerned, the learning level is too low. They are thinking that it is because of the non-detention policy that the learning level of the students is low. It is their thinking that teachers are not teaching and students are not learning because of the present non-detention policy, which is absolutely wrong. Sir, the present Right to Education Act has a clear provision for continuous and comprehensive evaluation, which is considered as a scientific method of evaluation, and it is widely accepted also. I am talking on the basis of the experience from my own State where 95 per cent of the total students are passed in SSLC examination, and almost 100 percent children within the relevant age group are enrolled in schools. So, I am talking on the basis of that experience; please consider this. We should not go for a detention policy which will be harmful to the children of our country. In fact, in many of our schools, this continuous and comprehensive evaluation process is not there. It is not being properly implemented. That is one of the important reasons. You are identifying a problem that yes, there is a problem as far as the school education is concerned. I agree with you that problem is there, but what is the kind of remedy that you are proposing! You have identified that you have got some headache, but your remedy should not be beheading. Unfortunately, you are proposing beheading as a remedy. It should not be like that. Sir, 16 years are over after the Constitutional Amendment was made and nine years are over after the passage of the Right to Education Bill, but till today, more than 2.8 crore children are out of school. They are not going to school. And what is the dropout ratio? It is more

[Shri K.K. Ragesh]
than 42 percentage, and if you are going to again implement this detention policy, what will happen to this? The dropout ratio is going to be alarmingly increased. Yes, as per the present Act, every child ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ragesh, you have to conclude.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, two more minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just conclude. One minute more. ...*(Interruptions)*... Please conclude.

SHRI K.K. RAGESH: This is a very important Bill. Sir, we should not pass this Bill like this. And many Members are not speaking. ...*(Interruptions)*... So, please allocate time. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is the time which has been allocated to you. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.K. RAGESH: Sir, please. This is a very important issue. Every child has got a right to quality education. And what is the kind of quality that we are assuring in schools? Is it that the teachers or the students responsible for the lack of quality in schools? It is there right from the Kothari Commission Report. The Kothari Commission had recommended for ensuring six percentage of the GDP on education and ten percentage of the Central Budget on Education. But what is the present situation? Till today, we are in a position to provide less than four percentage of our Central Budget on education. We are not in a position to meet the target of six percentage of the GDP on education. What is the status of many of our schools?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Mr. Ragesh. Please conclude.

SHRI K.K. RAGESH: We have got schools with single teacher; we have got many schools without a Headmaster; we have got many schools without any infrastructure. Sir, these are the main reasons for such a state of affairs. The reason is not the no-detention policy. So, you have to identify the real issue and address the real issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ragesh, I will invite another speaker now. Please conclude. Please conclude. Otherwise, I will invite another speaker. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I can tell you, in Kerala, all the children in the relevant age-group are enrolled in schools. They are going to schools and 95 percentage of the

total students are passing SSLC examination. We are implementing no-detention policy, not the detention policy. So, the detention policy is not the ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, you have concluded. I will now request Prof. Manoj Kumar Jha. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.K. RAGESH: Our responsibility is to ensure quality in education, provide all funds. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Prof. Manoj Kumar Jha, please speak. ...*(Interruptions)*... Otherwise, I will invite somebody else. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... He has already taken two more minutes. ...*(Interruptions)*...

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): उपसभापति महोदय, बड़े अच्छे माहौल में पिछले बिल पर बात हुई, लेकिन इस बिल पर, माननीय मंत्री जी, माफी के साथ कहता हूं कि मैं इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे चंद वजहें हैं। मंत्री जी, न जाने कौन-से आंकड़े आप लोगों ने देखे कि आपने तय किया कि No Detention Policy, Clause 16, should be done away with.

सर, आपने परीक्षा दी होगी, मैंने भी अपनी जिंदगी में परीक्षा दी है, हम, आप जिस वर्ग परिवेश से आते हैं, अगर हमें परीक्षा से डर लगता था, तो इन बच्चों के बारे में सोचिए। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ऐसा करके अपने सिस्टम की असफलता का ठीकरा उन बच्चों के सिर पर फोड़ रहे हैं। यह आपकी प्रणाली का दोष है, हमारी प्रणाली का दोष है, लेकिन इस दोष के लिए आप उन बच्चों को पीड़ित कर रहे हैं।

महोदय, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि हम जितने लोग इस सदन में बैठे हुए हैं, हमारे आपके बच्चे इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, जो बच्चे अलग वर्ग, चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हाशिए के समूहों में आते हैं from the margins और हमारा नज़रिया यह है कि हमने उन्हें फुटबॉल बना कर रख दिया है। आज एक किक मारा एक नई पद्धति में, कल दूसरा किक मारा एक दूसरी पद्धति में। मंत्री जी, ऐसा नहीं है, आप तो अभी साढ़े चार साल से हैं, मैं तो पूरी सियासत, जो शिक्षा के बारे में रही है, जिसने हमारे मुल्क में जाति-व्यवस्था को और पुख्ता किया, उसके पीछे यह वजह है कि हम यहां बैठ कर कानून बना देते हैं कि बच्चों, No Detention has to be done away with.

परीक्षा क्या चीज़ होती है? यह संसाधन पर डिपेंड करता है, शिक्षकों की उपलब्धता पर डिपेंड करता है। 9-9, 10-10 लाख शिक्षकों की vacancy है, यह किसका दोष है? उस बच्चे का, जिसको आप फेल करना चाहते हैं? उपसभापति महोदय, पढ़ाने के लिए छत नहीं है, एक छत में तीन क्लासेज़ चल रही हैं, तीन कक्षाएं चल रही हैं, तो मूलत: अगर यह तय कर लिया गया है कि इस मुल्क में असमानता के महासागर में पाँच समृद्धि के टापू के चालीसा पढ़े जाएंगे, तो जाइए आपकी मेजॉरिटी है, यह आप पास करवा लीजिए, लेकिन मैं सदन में यह कह रहा हूं कि आप पछताएंगे। आपने आज

[प्रो. मनोज कुमार झा]

एक regressive decision लिया है। This is a regressive decision. Why do I say that? आप बोर्ड परीक्षा का चरित्र समझिए। मैंने सातवीं कक्षा में बिहार में बोर्ड की परीक्षा दी थी, मुझे पता है कि मुझे कितनी दिक्कत हुई थी। मेरे माता-पिता दोनों शिक्षक थे। उस समय मेरी रूह कांपती थी। मेरा भूगोल का शिक्षक अच्छा नहीं था। आप छठी में बोर्ड ले आएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ऊपर के लेवल के लोग बैठकर बोर्ड परीक्षा के लिए तय करते हैं।

श्री उपसभापति: माननीय झा साहब, आप समय के अंदर बोलने के लिए जाने जाते हैं, कृपया समय का ध्यान रखें।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, माननीय मंत्री महोदय को पता है कि कितने प्रतिशत स्कूल RTE-compliant हैं। सर, इस बात पर गौर फरमाइए। Number one, only ten per cent schools are RTE-compliant. Number two is teacher vacancy, which I have already spoken about. Then there is the Union Budget about which many of my colleagues have spoken. But I wish to tell you, if you look at the number of the children who are out of school today, this one policy of taking away the no-detention clause will make sure that you have millions added to that list. And on that list you won't find my kid's face or your kid's face. These are the kids who are the future of India, but we do not acknowledge them because they come from subaltern communities and groups. I request this House, Sir, to discuss it further, but if you proceed with taking away the no detention clause, I think it is going to do irreparable harm to the very cause for which it was brought in.

Thank you very much. Jai Hind.

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): उपसभापति महोदय, आरटीई एक्ट दुनिया के बहुत से देशों में लागू था, हमारे देश मे भी उसका कॉपी पेस्ट किया गया है। यह एक्ट बहुत बढ़िया है। देश के अंदर जिस भावना से यह एक्ट बना, अगर उसी भावना से लागू होता, तो उस हिसाब से infrastructure develop होता।

उपसभापति महोदय, एआईसीटीई और दूसरी टीचर ट्रेनिंग संस्थाएं, टीचर्स को ट्रेनिंग देती हैं। बच्चों को comprehensive शिक्षा मिलती, evaluation होती, तो यह एक्ट बहुत बढ़िया था। इस एक्ट में कोई कमी नहीं थी, कोई detention होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कई बच्चे परीक्षाओं से डरकर सुइसाइड तक कर लेते हैं। वे बोर्ड की परीक्षाओं से डरते हैं, बाकी परीक्षाओं से डरते हैं, परंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि न तो एनसीटी ने ऐसे कोर्स बनाए, जो बच्चों को पढ़ा सकें, टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकें और किस लेवल पर इस देश में शिक्षा का स्तर होना चाहिए था, जिसमें वे उठ सकें, न ही स्कूलों के लिए infrastructure create करने की तरफ राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने कोई ध्यान दिया। आरटीई एक्ट में यह प्रोविज़न था कि एक किलोमीटर, तीन किलोमीटर, पांच किलोमीटर के दायरे के अंदर प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल और प्रिपेरेटरी स्कूल शुरू से होने चाहिए, जो पूरे हिन्दुस्तान में नहीं हो पाए हैं। इस एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत बच्चे फ्री पढ़ाने का

प्रोविज़न था, जिसकी मॉनिटरिंग राज्य सरकारों को करनी थी। मुझे यह कहते हुए खेद है कि 36 राज्यों में से 20 राज्यों ने आरटीई एक्ट को लागू ही नहीं किया और जिन 16 राज्यों ने लागू किया, उन राज्यों मे भी उस पर सरकारों की निगरानी नहीं है। दिल्ली सरकार कंप्यूटर के माध्यम से एंश्योर करती है कि सभी अमीर और बड़े-बड़े पोलिटिशियन के बच्चों के साथ गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ें और उन 25 परसेंट बच्चों को बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिले, इस बात को दिल्ली सरकार एंश्योर करती है। इस एक्ट के तहत सारी की सारी राज्य सरकारों को एंश्योर करना चाहिए था, ताकि आरटीई एक्ट के तहत समान शिक्षा का अधिकार पूरे हिन्दुस्तान में लागू हो सके। इसके तहत जो 25 परसेंट बच्चे पढ़ते हैं, उनका खर्चा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को मिलकर देना चाहिए था और जिन सोलह राज्यों में यह आरटीई एक्ट लागू हुआ है, उनमें भी यह पूर्णत: नहीं दिया जा रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि दिल्ली सरकार हर महीने 2242 रुपए एलकेजी से लेकर पाँचवीं कक्षा तक के हर गरीब बच्चे के लिए उस प्राइवेट स्कूल को देती है, जहां पर गरीब बच्चे को पढ़ाया जाता है। उसकी यूनिफार्म के लिए 1,100 रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार, मिडिल क्लास, यानी पाँचवीं से लेकर आठवीं कक्षा के लिए 2,225 रुपये दिए जाते हैं और उसकी यूनिफार्म के लिए 1,400 रुपये दिए जाते हैं, ताकि उन बच्चों को महसूस हो कि हम भी बढ़िया स्कूलों में पढ़ने का हक़ रखते हैं। इस प्रकार, देश में एक समान शिक्षा की बात वहाँ पर आती है।

श्री उपसभापति: माननीय सुशील गुप्ता जी, आपका समय खत्म हुआ।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: सर, मैं एक मिनट और ले रहा हूं। जनाब, मैं कहता हूं कि यह ऐक्ट बहुत बढ़िया था। इस ऐक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है - संसाधनों के अभाव के अंदर, इस ऐक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ रही है - कोशिश के अभाव के अंदर। यह फैसला राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने शिक्षा के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं, विशेषकर स्कूली शिक्षा के अंदर, मैं इस हाउस के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि पूरा हिन्दुस्तान शिक्षित होगा और यह तभी हो सकता है जब शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए जाएँ। दिल्ली सरकार अपने बजट में से 25 परसेंट पैसा शिक्षा के ऊपर सीधा-सीधा लगाती है, जबकि अन्य सरकारें नहीं लगा पातीं और भारत सरकार 3.7 परसेंट लगाती है। मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान को शिक्षित करने के लिए हमारे बजट के अंदर इस मद में थोड़ी-सी बढ़ोत्तरी की जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अब आप अपनी बात खत्म कीजिए, अब मैं अगले स्पीकर को बुलाऊंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुशील कुमार गुप्ता: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): सर, आज सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक लाया है, उस पर मुझे बोलने का अवसर मिला, उसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हम बिना ज्ञान के आँख रहते हुए भी अंधे कहलाएंगे। मैं उस राज्य से आती हूं, जहां पर आदिवासी, जहां पर जंगल, जहां

[श्रीमती छाया वर्मा]

पर अनुसूचित जाति और जहां पर अधिकांशत: गरीब लोग निवास करते हैं। वहां पर प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं और सरकारी स्कूल्स जंगल में हैं, बहुत दूर-दूर पर हैं, इसलिए वहां पर अनिवार्य रूप से बिना परीक्षा के पास करने को मैं प्राथमिकता देती हूं, लेकिन वहां टीचर्स की उपलब्धता हो और उन स्कूलों को साधन-सम्पन्न बनाया जाए। जब हम परीक्षा लेते हैं और अगर कोई बालक पाँचवीं कक्षा के बाद फेल हो जाएगा, तो उसके मन में एक हीन भावना घर कर जाएगी, वह अपने आपको अन्य बच्चों से अलग महसूस करेगा और इस तरह से dropouts की संख्या बढ़ेगी, इसलिए उनको आठवीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से पास करते जाना चाहिए।

मैं इस सदन को एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि शिक्षा इंसान के लिए कितनी जरूरी है। एक आदिवासी महिला, जो कि पढ़ी-लिखी नहीं थी, उसके यहां एक बार एक डाकिया डाक लेकर आया और उस महिला को एक चिट्ठी पकड़ा गया। वह महिला उस पत्र को हाथ में लेकर रोने लगी और जब उसके पास उसके पड़ोस की महिलाएं आईं, तो वे भी रोने लगीं। इस तरह से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और सब लोग रोने लगे। वे किसलिए रो रहे हैं, यह किसी को पता नहीं था। जब बाद में उस महिला का बेटा आया, तब उसने उनको बताया कि इस चिट्ठी में यह लिखा है कि पापा को नौकरी मिल गई है, उसके बाद सब लोग खुश हुए। मेरे कहने का मतलब यह है कि कम से कम पढ़ने लायक शिक्षा प्राप्त करना और साक्षर होना बहुत जरूरी है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करती हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि वे इतना अच्छा बिल लाये। यह ठीक है कि आदिवासी स्कूलों में बच्चे पढ़ाई में आठवीं कक्षा तक पास हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ तीरंदाज़ी जैसी अन्य विवध कलाएं भी होती हैं, जिनमें आदिवासी बच्चे देश भर में अपना नाम रोशन करते हैं और इस तरह से अन्य प्रतिभाओं को भी बढ़ने का अवसर मिलता है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद देती हूं।

श्री उपसभापति: छाया जी, शिक्षा का essence बताने के लिए धन्यवाद। माननीय श्री एन. गोकुलकृष्णन।

SHRI N. GOKULAKRISHNAN (Puducherry): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 was having a provision of 'no detention policy'. That means, no child can be held back in classes 1 to 8 until completion of elementary school.

The new Bill of 2018 has proposed an Amendment of sub-Sections 1 to 4 under Section 16 of the Act, which empowers the Central and the State Governments to allow school to hold back child in class 5, class 8 or in both classes.

It also mandates conducting regular examination in class 5 and class 8 at the end of every academic year. In case the child fails in class 5 or class 8 examination, that child will be given additional chance or an opportunity to appear for re-examination within a period of two months from the declaration of the result. Sir, the Bill also empowers the

Union and the State Governments to decide whether to hold back or not to hold back child in any class till completion of elementary education. This Bill also gives free hand to the respective Governments to take any decision as there is no consensus arrived among States with regard to going for 'no detention policy' or to hold back the child. I am worried that this Amendment is again getting diluted because the question of how many States are going to implement this Amendment and how many of them are going to keep 'no detention policy' is still not known. Sir, the experts have recommended rolling back the 'no detention policy' either partially or completely. The reasons are (i) lack of preparedness of the education system to support the policy; (ii) automatic promotion system derails children from working hard; (iii) low accountability of teachers; (iv) low learning outcomes; and (v) lack of proper implementation of continuous and comprehensive evaluation and its integration with teacher training. Sir, till the year 2017, continuous and comprehensive evaluation mechanism prevailed, but it was later on withdrawn by the Government. No doubt that 'no detention policy' is more useful to bring down the school dropouts. On the other hand, we cannot hide the fact that the standard of elementary education has also dropped to a larger extent. Now, there are 66.41 lakh teachers employed both in Government and private schools. Among those teachers, about 11 lakh teachers are still untrained and they have been given an opportunity to get trained before March, 2019. Further, the Government had extended online facility to the teachers to train themselves in the name of *Swayam* Platform. In this regard, I would like to know how many of the untrained teachers have availed this opportunity and qualified themselves. Whether the Government intends to extend the deadline further to enable the left out teachers to qualify? Sir, the statistics says that in the primary level, the school dropouts is only 4 per cent, whereas it shoots up to 17 per cent in the secondary level. It is mainly because of automatic promotion from Class 1 to Class 8. But, it is not in the case of secondary level, that is, from Class 9 onwards. They have to undergo examinations for getting promotions. The sad fact is that the children are not up to the standard to take on examinations. In fact, this was the system that was in vogue before the present Act came into existence. Though, we found fault with that system, the students concentrated on their studies and showed semblance of involvement in reading, out of fear of examinations. This helped them to cope with the learning process to a greater extent. But, the free pass given by the present Act in the form of 'no detention policy' could not bind them to a continuous process of learning. Apart from the examination factor, the other major factor for dropouts is the poor economic background of the families wherein the children are compelled to take menial jobs to support their families. Though the Child Labour Act prohibits employment of children, the system of child labour still exists. Providing mid-day meals, giving free

[Shri N. Gokulakrishnan]

uniform sets, books and notebooks and conducting evening courses would only partially address the issue. Sir, the Economic Survey Report 2015-16 pointed out that only 42 per cent of students from Government schools in Class 5 are able to read a Class 2 text. It reveals that the performance of the students on an average had gone down and they have not been trained properly. This is where the Government school teacher's commitment to the profession and accountability to the society become vital. If we compare private school teachers and Government school teachers, the performance of the private school teachers is more admirable than the latter. In fact, the Government school teachers are getting more salary than that of the private school teachers.

Sir, regarding students' performance, it is better to evaluate a child over a graded system instead of numerical marks pattern, which paves way for comparison among the student community. It affects their morale. This may, in the long run, dissuade a child from the process of learning.

Sir, I would like to submit some of the inputs arrived at by *Maadhyam*, a forum for citizens to engage in policy making. *Maadhyam* undertook a thorough stakeholder consultation and submitted a report. This report summarises the reasons for supporting withdrawal of 'no detention policy', wherein it increases teacher's accountability, proper assessment of children through exams thereby establishing a link between performance and outcome. Thereby, it seeks to ensure better learning.

Sir, children are the future of the country and if they are not competent enough, owing to 'no detention policy', there will be a dearth of intellectuals. Hence, *Maadhyam* opined that exams are necessary.

Before I conclude, I would like to bring to the notice of this august House that the new generation children have more I.Q. compared to that of older generation. Hence, I would like to strike an analogy between the robust foundation required for an engineering marvel and the strong education foundation of students for a better future.

For this purpose, I request the Minister of Human Resource Development to enlarge the scope of free and compulsory education from pre-primary to secondary level within the age group of 3-16 years. I am suggesting this because most of the job recruitments, both in Government as well as in the private sector, demand at least a pass in tenth standard. In this context, Tamil Nadu Government is a pioneer, as it is planning to bring pre-primary into the elementary education from the ensuing academic year.

Before I conclude, I feel that giving option to the State Government on 'no detention policy' should be coupled with the improvement in the quality of teaching education and retention of the students.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Gokulakrishnanji. Please conclude.

SHRI N. GOKULAKRISHNAN: If that is ensured, I hope that the students' performance and the dropout ratio at the secondary level will certainly improve as envisaged by the proposed Amendment.

With these words, I conclude and I support this Amendment on behalf of my party.

श्री उपसभापति: माननीय अनुभव मोहंती जी, आपकी पार्टी के पास एक ही मिनट का समय बचा है, परन्तु आप इतने सक्षम हैं कि दो मिनट में अपनी बात बहुत सुन्दर तरीके से कह सकते हैं।

श्री अनुभव मोहंती (ओडिशा): सर, देश के बच्चों का मामला है। थोड़ा सा consider कीजिएगा।

श्री उपसभापति: हमने पहले से ही समय बढ़ा कर दो मिनट कर दिया है।

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act got passed in 2009, implemented in 2010, and a very big Amendment came in 2018. So, the entire move has been based on popular perception of traditional system of examination, which has no scientific base at all. Nobody has conducted any study to see the impact of 'no detention policy' in schools where Continuous and Comprehensive Assessment (CCA) has been followed in letter and spirit. Sir, the CCA is a child-friendly assessment process of assessing the competence of the children at different points of time during the year in a comprehensive manner instead of half-yearly and yearly examinations. The traditional examination is basically meant for class promotion and detention. The CCA is meant for taking corrective measures, for improvement of performance of children by the teachers at different points of time during the year. Therefore, CCA is more progressive in nature and many nations have been adopting this since long.

Sir, 'no detention policy' was supposed to be complemented by Continuous and Comprehensive Assessment which is based on the principle that if the children are not learning, it is not their fault; rather fault lies somewhere else, such as parents, teachers, school environment, curriculum, text-books and teaching learning process. Sir, only 10 per cent of the schools in the country comply with the RTE Act even after seven years of implementation of the Act, which has a detrimental effect on the learning of children. Instead of ensuring implementation of the Act, the Government is trying to blame 'no detention policy'. I fear if the Government will come in the future with more...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, I will conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You have already taken two minutes.

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, if this happens, then the situation of the school education will get worsened. If examination detention system will be introduced, more children will be pushed out of the school, drop-out rate will increase which is against the spirit of RTE Act. So, Sir, I will only support the Bill, if the Government assures the House that this amendment will be beneficial for the children of our country. Sir, our children are the future of our nation. We cannot just play with their lives and their future for our own faults. We cannot penalise children for the system's faults. We have to correct ourselves first and whatever amendments you have brought have to be properly implemented, properly executed and you have to assure the House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank You.

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, finally I will close. Sir, finally, the Government must increase the budget for the children's education, when we are talking about free and compulsory education to the children. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Mohanty. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, for the Odisha Adarsh Vidhyalaya, the Government had promised to give a good amount to the Odisha Government but they did not continue after very short time ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: अब मैं अगले स्पीकर को invite करूंगा।

SHRI ANUBHAV MOHANTY: The hon. Minister has already visited the Kalinga Institute of Social Sciences, (KISS) ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: माननीय अशोक सिद्धार्थ। Please conclude. ...*(Interruptions)*... अशोक सिद्धार्थ जी, आप अपनी बात कहिए। आपकी बात ही रिकार्ड पर जा रही है। ...**(व्यवधान)**... अशोक सिद्धार्थ जी, कोई और बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी, केवल आपकी बात रिकार्ड पर जाएगी।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके और सदन के माध्यम से पूरे देशवासियों को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वे देश की पहली महिला शिक्षिका थीं। वे अशिक्षित थीं और उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले ने उन्हें शिक्षित बनाने का काम किया था।

7.00 P.M.

श्रीमन्, मैं अपनी पार्टी की लीडर आदरणीय बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए अधिकृत किया है। श्रीमन्, शिक्षा मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शिक्षा मनुष्य को मान और अपमान में भेद का एहसास कराती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस देश में सामाजिक और शैक्षणिक गैर-बराबरी हमेशा से रही है। इस देश में पहली बार किसी ने अगर शैक्षणिक गैर-बराबरी को समापत करने के लिए संघर्ष करने का काम किया तो वह महात्मा ज्योतिराव फुले थे। दूसरे छत्रपति साहूजी महाराज हैं। महोदय, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां एक तरफ आज़ादी को लगभग 72 वर्ष बीत गए हैं, तब हम 'The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill' ला रहे हैं, जबकि श्री छत्रपति साहूजी महाराज ने अपनी रियासत में 24 जुलाई, 1917 को प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य लागू करने के लिए न सिर्फ Education Reform Committee बनाने का काम किया, बल्कि गुणवत्तापरक शिक्षक एवं शिक्षा दिए जाने के लिए उन्होंने कानून भी बनाया। क्योंकि वे पिछड़े समाज से ताल्लुक रखते थे, कुनबी समाज से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उन्होंने वंशानुगत शिक्षकों की भर्ती के स्थान पर सेलेक्शन कमेटी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती स्टार्ट करने का काम किया था। उन्होंने अपनी रियासत में गुणवत्तापरक शिक्षा सभी समाज के लोगों को देने का काम किया।

माननीय उपसभापति महोदय, इन्हीं महापुरुषों के बताए रास्तों पर चलकर हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की चार-चार बार लोकप्रिय, जनप्रिय, न्यायप्रिय मुख्य मंत्री रही परम आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी जब-जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देने का काम किया। इसके लिए उन्होंने 88,000 बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करने एवं माता सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना के अंतर्गत 25 हज़ार रुपए और एक साइकिल दिए जाने का प्रावधान किया था। जो आज हम "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का नारा लगाते हैं, आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार में उस समय बेटी बचाने के साथ-साथ बेटी पढ़ाने का काम प्रारम्भ करने का काम किया था। यह विडंबना है कि आज देश में स्कूलों में, जैसा कि विदित है, छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की भारी कमी है। उत्तर प्रदेश, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें लाखों की संख्या में...

श्री उपसभापति: माननीय अशोक जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अशोक सिद्धार्थ: सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। लाखों की संख्या में शिक्षकों की कमी है।

मैं अपने इन सुझावों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं। जो मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूल होते हैं, उनमें मान्यता प्राप्त करने वालों की जो पद्धति बनाई जाती है, उसमें ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाए, जो न रिश्वत लेते हों और न लेने दें। दूसरा, एक तरफ हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि One Nation, One Tax और एक भारत, श्रेष्ठ भारत। लेकिन आज तक हमारे भारत के प्रधान मंत्री जी ने, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यह कभी नहीं कहा कि One Nation, One Education .One Nation, One Education तब तक नहीं होगा, जब तक हम प्राथमिक शिक्षा पर बल नहीं देंगे और quality education is not possible without having one education system in the country. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपसभापति: माननीय राम कुमार कश्यप जी।

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): धन्यवाद, सर। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल में आठवीं क्लास तक फेल नहीं करने की नीति में संशोधन करने की बात कही गई है। जब इसमें संशोधन हो जाएगा तो बोर्ड के माध्यम से पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं ली जाएंगी। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)...

SHRI VIJAY GOEL: Sir, I propose to extend the time till the debate is over. ...(Interruptions)... Till the Bill is passed. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति: मुझे लगता है कि आम सहमति बनेगी। सदन की राय है तो इसे हम और बढ़ाएंगे। कश्यप जी, आप अपनी बात खत्म करें।

श्री राम कुमार कश्यप: सर, इस बिल के आने से बोर्ड के माध्यम से पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं ली जाएंगी और परीक्षा में जो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको फिर दुबारा दो महीने का टाइम देकर उसकी परीक्षा ली जाएगी। अगर पुन: वह फेल हो जाता है, उसको स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, परंतु उसको वापस उसी क्लास में रखा जाएगा। मैं समझता हूं कि इस बिल के आने से शिक्षा के स्तर में बहुत ...**(व्यवधान)**...

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, it is seven o'clock. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have taken the sense of the House. ...*(Interruptions)*... We will dispose of this Bill. ...*(Interruptions)*... You are such a senior Member. ...*(Interruptions)*... We have decided that. ...*(Interruptions)*...

SHRI VIJAY GOEL: Sir, he will be the last speaker. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. D. Raja. ...*(Interruptions)*... हम लोगों ने sense of House लिया है। राजा साहब, प्लीज़ आप बोलिए। ...*(Interruptions)*... Shri D. Raja, please speak. ...*(Interruptions)*... He will take just two minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Then you postpone it. ...*(Interruptions)*... We will have it on Monday. ...*(Interruptions)*...

श्री राम कुमार कश्यप: सर, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपका समय खत्म हुआ। ...**(व्यवधान)**... राजा साहब, आप अपनी बात कहिए। ...**(व्यवधान)**... राजा साहब की बात के अलावा कुछ और रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S. R. BALASUBRAMONIYAN: *

SHRI K. K. RAGESH: *

श्री उपसभापति: राजा साहब, आप अपनी बात कहिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI D. RAJA: Sir, everybody is speaking. ...*(Interruptions)*...

SHRI K. K. RAGESH: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ragesh, I am not allowing you. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record except what Shri D. Raja says. ...*(Interruptions)*... Shri D. Raja. ...*(Interruptions)*... आज sense of House के तहत यह तय हुआ है। ...**(व्यवधान)**... आज हम लोग इतने अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... Let us finish it. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: I am ready. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri D. Raja, I am telling you to start speaking. ...*(Interruptions)*... हम लोगों ने समय लिया है। ...**(व्यवधान)**... Rageshji, I am not allowing you. ...(Interruptions)... इस बिल के लिए तीन घंटे का समय तय किया था। ...**(व्यवधान)**... इसे घटाकर अब एक घंटे का समय तय किया था। ...**(व्यवधान)**... राजा जी, अब आप बोलें। ...**(व्यवधान)**... Rajaji, please. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record except what Shri D. Raja says. ...*(Interruptions)*... Rajaji, please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Sir, we heard a number of speeches. ...*(Interruptions)*... Probably I am the last speaker. I rise to oppose this Bill. I do not agree with the understanding of the Government on this issue. Sir, ideally speaking, this Bill should have been referred to a Select Committee for further scrutiny by consulting educationists, psychiatrists and psychologists with regard to children and their welfare.

Sir, what is this Amendment? This Amendment is for detention of children, thereby increasing the number of dropouts of our children. In fact, education is not a privilege; it is a right. But there is a distressing trend in our country. Education is becoming increasingly privatized and commercialized. We do not have access to quality education for all our children. Children are children, our children. They must have access to quality education. We do not have common school system. Government should have thought of common school system. Government should have thought of other things. The previous Government brought forward a Bill for free and compulsory primary education and I thought this Government will bring forward a Bill for free and compulsory secondary and

*Not recorded.

[Shri D. Raja]

higher education. That would have been a credit for Mr. Javadekar, my good friend, but he has not brought forward such an amendment. He is bringing forward an amendment for detention. That is why I am saying that even at this stage, the Minister can defer this Bill for further consultation and for further scrutiny. He can defer this Bill. I am telling you. Now, you appointed a commission under the chairmanship of Mr. Kasturirangan, who was our colleague in Rajya Sabha. What happened to that report? ...*(Interruptions)*... It is ready! Where is that report?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please address the Chair.

SHRI D. RAJA: Earlier, we had a commission headed by Mr. T.S.R. Subramanian. I do not know what happened. Some recommendations were not agreeable to the Government. You shelved that report. Now, the Minister says that the Kasturirangan Report is ready. When are we going to see that Report? We don't know. What I am trying to say is that the Government does not have a mechanism to update the syllabus when and where it is necessary. Even today in Class-XI, I can say that the history book says that Aung San Suu Kyi is under house arrest. Maybe, she was under house arrest some time back. Now, she is not under house arrest. But, the same thing is taught in class. How can you blame the children for all such things? Even when Free and Compulsory Primary Education Bill was discussed in this House, I raised the question about the children in the age groups of 0-6 and 14-18 years. Does the nation have concern for these children or not? It is left to the State Governments because education is in the Concurrent List. For children in the age group of 0-6 years, there may be *anganwadi* and midday meal schemes, but it is left to the State Governments. What about the Union Government? The Union Government should have taken the responsibility. Many people have asked the question. Kothari Commission made a recommendation in 1966 that six per cent of GDP be spent on education. Today, we are in 2019. What is the percentage of GDP you are spending on education? Public education and public health are being undermined and given up. This is a very dangerous trend. That is why, I think this Bill needs to be further scrutinized and there is a need for proper consultations with State Governments and with all the stakeholders. I urge upon the Minister to defer this Bill. Let us apply ourselves; collectively, we will think over it. We will put all our heads and efforts together. After all, we are working for the welfare of the children. They are the future of the nation. So, I appeal to the Minister to think over this. With these words, I conclude.

श्री उपसभापति: माननीय हुसैन दलवई साहब। आप अंतिम स्पीकर हैं। आप दो मिनट बोल लीजिए।

(**श्री सभापति** *पीठासीन हुए*)

श्री सभापति: हुसैन दलवई जी को दो मिनट का समय नहीं दीजिए। इनको तीन मिनट का समय दीजिए।

श्री हुसैन दलवई: सभापति जी, यह सरकार इस अमेंडमेंट के जरिए, जो वर्ष 2009 में लॉ बनाया गया था, उसे खत्म करने की बात कर रही है। यदि ऐसा किया जाएगा, तो वर्ष 2009 का कानून नेगेट हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार और मंत्री महोदय से अपील करूंगा और उन्हें यह मालूम ही होगा कि सावित्रीबाई फुले की आज जयन्ती है। जब मैं सावित्रीबाई फुले का नाम लेता हूं, तो उनके साथ फातिमा शेख का नाम भी लेता हूं, क्योंकि फातिमा शेख हमेशा सावित्रीबाई फुले के साथ ही रहती थीं। महात्मा फुले ने एजुकेशन के लिए जो काम किया था, उसमें महिलाओं की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया था, इसलिए मैं उनका अभिवादन करता हूं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि continuous and comprehensive evaluation की व्यवस्था कानून में पहले से ही है। यदि पांचवीं कक्षा के बाद आप उन्हें बाहर निकालेंगे, तो बिल्कुल गलत होगा। एक तो यदि बच्चा फेल है-फेल है यह कहेंगे, तो उस बच्चे के दिमाग में यह बात जाएगी कि मैं फेल हो गया हूं और उसके मां-बाप भी बोलेंगे कि जब मेर में दिमाग ही नहीं है, तो तू क्यों पढ़ता है। अपने देश में ऐसी हालत है। उसे आप देखिए। मेरा कहना है कि बच्चों का हर महीने एग्जामिनेशन लेना चाहिए। यह कम्पल्शन टीचर्स के ऊपर होनी चाहिए। श्री जावडेकर जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरी पोती चार साल की है। वह चार लेंग्वेजेज बोलती है। वह मराठी बहुत अच्छी बोलती है, वह इंग्लिश अच्छी बोलती है, वह हिन्दी अच्छी बोलती है और तेलुगु भी बहुत अच्छी बोलती है, क्यों? क्योंकि उसके घर के सारे लोग पढ़े-लिखे हैं। जिनके घर के लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, वहां टीचर्स को उनके मां-बाप बनना चाहिए और उन्हें पढ़ाना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। उन्हें पढ़ाने के लिए कहीं लाइब्रेरी नहीं होती, कहीं अच्छी लेबोरेटरीज नहीं होतीं, कहीं अच्छी इमारत नहीं होती और कहीं-कहीं तो उनके बैठने के लिए बैंचेज़ भी नहीं होतीं।

महोदय, मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि मुस्लिम बच्चों की इस बारे में हालत बहुत खराब है। देश में 30 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे चाइल्ड लेबर हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति ही नहीं है कि वे पढ़ सकें। इसलिए आपको यह देखना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार से पढ़ने में मदद की जाए। आप ऐसा न करके जो उल्टा काम कर रहे हैं, वह मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है।

मुझे मालूम है कि यह डिमांड सारे लोगों ने की है। इसलिए आप इस अमेंडमेंट को कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग जो कहते हैं, वह सही हो, यह भी ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को कहीं न कहीं दो कदम आगे बढ़ कर सोचना चाहिए। मैं कहूंगा कि आप इस अमेंडमेंट को पास करने के बजाय, स्कूलों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दीजिए। मेरा तो यह कहना है कि दिल्ली में जैसे बजट में 25 परसेंट पैसा एजुकेशन पर खर्च किया गया, तो उसका दिल्ली में अच्छा असर देखने को मिल रहा है। वैसा आप भी कीजिए। कहीं न कहीं कुछ कमियां तो रहेंगी। वे धीरे-धीरे ही ठीक होंगी।

महोदय, जब मैं पढ़ता था, तो मुझे यह बताया जाता था कि इस देश में एक स्टेट केरल ऐसी है, जो सबसे ज्यादा पढ़ी है और दुनिया में एक देश चीन ऐसा है, जो सब से गरीब है। आज एजुकेशन की वजह से दोनों आगे गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश में एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। इसलिए कहीं न कहीं आप ऐसा प्रयास कीजिए जिससे देश के हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके।

श्री सभापति: श्री हुसैन दलवई, कृपया बैठिए।

श्री हुसैन दलवई: महोदय, आपको तो मालूम है कि कम्पल्सरी एजुकेशन के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, उनसे पता लगता है कि कम्पल्सरी एजुकेशन के लिए जो पैसा रखा गया था, वह भी खर्च ही नहीं हुआ। वह क्यों खर्च नहीं होता, उसमें क्या दिक्कत है, आप उसे देखिए। मेरे ख्याल से आप इस अमेंडमेंट को न करें, और पीछें जाएं, तो बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद।

श्री सभापति: नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे क्यों जाना चाहिए।

श्री प्रकाश जावडेकर: सभापति जी, मैं सभी माननीय सदस्यों - श्री महेश पोद्दार, श्री जावेद अली खान, श्री मो. नदीमुल हक, श्री प्रसन्न आचार्य, श्री राम नाथ ठाकुर, श्री के.के. रागेश, प्रो. मनोज कुमार झा, श्री सुशील गुप्ता, श्रीमती छाया वर्मा, श्री एन. गोकुलकृष्णन, श्री अनुभव मोहंती, श्री अशोक सिद्धार्थ, श्री राम कुमार कश्यप, श्री डी. राजा और श्री हुसैन दलवई का आभार व्यक्त करता हूं। इस विषय पर बहुत अच्छी चर्चा हुई और मुझे इस बात की बहुत खुशी है।

महोदय, मुद्दा क्या है, इस बिल को यहां क्यों लाया गया है, इस पर मैं संक्षेप में अपनी बात पांच मिनट में कहकर समाप्त करूंगा। यह बिल इसलिए आया कि जब शिक्षा की चर्चा करते हैं, तो सभी लोग रोजाना यह बताते हैं कि पांचवीं कक्षा के छात्र को तीसरी कक्षा का गणित नहीं आता या आठवीं कक्षा के छात्र को छठी कक्षा का पाठ पढ़ना नहीं आता। अगर यह learning outcomes है, तो यह क्यों है, इसका अध्ययन हुआ? सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने यहां दो दिन बैठक की और वे 25 राज्यों के मुख्य मंत्रियों के मैसेज लेकर आए थे और उसमें सभी पार्टियों के शिक्षा मंत्री थे। उस मीटिंग में सभी ने कहा कि हमें इस पद्धति में बदलाव चाहिए और इसे बदलने की हमें परमीशन चाहिए। चार राज्यों ने कहा कि नहीं, we are okay with no detention. इसलिए मैंने यह उपाय किया कि इसे हम राज्यों पर छोड़ेंगे। So, this Bill is nothing but to give power to the States. टीएमसी, जो रोज़ कहती है तो स्टेट को पावर दो, यही पावर तो दे रहे हैं कि स्टेट्स तय करेंगे कि no detention चालू रखना है या उसमें बदलाव करना है। आज के दिन तक मेरे पास जो सारी जानकारी आई है, उसके अनुसार 25 राज्य बदलाव चाहते हैं, 4 राज्य नहीं चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि हम यह अधिकार राज्यों को दे रहे हैं, दूसरी बात यह है कि आज सभी ने भाषण में यह कहा कि comprehensive evaluation होना चाहिए, यानी हर सप्ताह टीचर लिखेगा कि स्टूडेंट कैसे प्रोग्राम कर रहा है। यह नहीं हो रहा है, इसलिए यह बिल आया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, एक मिनट ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI PRAKASH VERMA: I have a question on this. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him complete. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI PRAKASH VERMA: Sir, I have an important issue to raise. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him complete. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, comprehensive evaluation पर मैं विश्वास रखता हूं, लेकिन हमारे 11 लाख सरकारी स्कूल हैं और अगर हम वहां देख रहे हैं कि अनेक कारणों से, उसकी चर्चा में बहुत समय जाएगा, लेकिन यह नहीं हुआ है। राज्य सरकारों की मांग थी, इसलिए हमने, केंद्र ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया। यहां स्टैंडिंग कमेटी में भी गया और स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टीज़ के प्रतिनिधि थे, उसमें राज्य सभा के 10 और लोक सभा के 20 सदस्य थे, सभी ने मिलकर एक राय से इस बिल को सम्मति दी है। इसमें क्या है, मैं इसके बारे में पहले ही बताना चाहता हूं कि यह बिल किसी को भी स्कूल से बाहर निकालने का नहीं है। यह परीक्षा लेने की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कंपीटीशन कोई किलर नहीं होता है। बच्चे खेल में भी रोज कंपीटीशन करते हैं। वे जब क्रिकेट खेलते हैं या कोई खेल खेलते हैं, तो आपस में कंपीटीशन भी करते हैं। It is a good spirit. वे इसी आनंद से परीक्षा दें। अगर कोई बच्चा उसमें पीछे रह जाता है, तो उसे दो महीने में remedial teaching देने की टीचर्स की जिम्मेदारी होगी। अब जिम्मेदारी के बाद, दो महीने के बाद वे इसको देंगे और देने के बाद अगर उसमें यह हुआ तो वह अधिकार हमने राज्यों को दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें किसी को बाहर निकालने का मुद्दा नहीं है। अभी तक यह हो रहा है कि आठवीं क्लास तक ड्रॉपआउट नहीं है, क्योंकि परीक्षा ही नहीं है, लेकिन नवीं में बीस परसेंट ड्रॉपआउट है और दसवीं क्लास में और बीस परसेंट ड्रॉपआउट है। क्या यह एक अच्छा चित्र है कि शिक्षा में जो पाठ पढ़े हैं, उनका कुछ भी आता नहीं है। हम यह कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हम केवल उनको आगे-आगे कर रहे हैं। यह सबकी मांग थी, यह पेरेंट्स की मांग थी। हम राज्यों को यह छूट दे रहे हैं। एक सवाल यह भी पूछा कि परीक्षा कौन लेगा? यह कोई बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, यह तो स्कूल की परीक्षा होगी, जैसे बचपन में हमारे स्कूल में होती थी, वैसे ही school will take the examination. सभी ने जो एक सुझाव दिया, वह मुझे मंजूर है कि शिक्षा के ऊपर ज्यादा खर्च होना चाहिए। 2014 में अपने यहां शिक्षा पर 82 हज़ार करोड़ का बजट था। अब, इस साल, जो नई व्यवस्था है, हायर एजुकेशन में फायनेंस भी किया, उसके मार्फत इस साल 30 हजार करोड़ की सैंक्शन हुई है। 1 लाख, 15 हज़ार करोड़, क्योंकि 85 हज़ार करोड़ रुपये मूल बजट है और यह नया मिला है, तो 1 लाख 15 हज़ार करोड़ रुपये उससे खर्च हो रहा है। यह 40 परसेंट इंन्क्रीज़ है। हमारा यह आग्रह है कि यह खर्च और भी बढ़ाना चाहिए। मैं आज इसलिए सबको धन्यवाद दूंगा कि सावित्रीबाई फुले जी का उनकी जन्म-जयंती पर सभी ने स्मरण सबने किया, उन्होंने फातिमा शेख के बारे में भी कहा। जो भी सारे शिक्षक हैं, जिन्होंने भारत में शिक्षा फैलाने का काम किया, उन सभी का स्मरण करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपने दोनों शिक्षा बिल पास किए हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN:The question is:

"That the Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are two Amendments (Nos. 1 and 2) by Dr. T. Subbarami Reddy; he is not there. So, the Amendments are not moved.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 1, there is one Amendment (No.3) by the Minister, Shri Prakash Javadekar.

CLAUSE 1 - SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, I move:

(3) That at page 1, line 3, *for* the word and figure "Act, 2018", the word and figure "Act, 2019" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.
The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI D. RAJA: Sir, we are not satisfied with the reply. Even the amendments are. ...*(Interruptions)*... That is why we are walking out. That is what I am telling you.

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, हम लोग भी इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम लोग भी सदन से walk out कर रहे हैं।

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।)

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Minister to move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, the message should be, no detention, but everybody will be retained; retention in the school.

The House stands adjourned till 1100 hrs on Friday, the 4th January, 2019.

The House then adjourned at twenty-two minutes
past seven of the clock till eleven of the clock
on Friday, the 4th January, 2019.